प्रेषक,

सोमपाल, अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनु0-3 देहरादून दिनांक र्८ फरवरी, 2013 विषय:-वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित योजना 'अल्पसंख्यक कल्याण भवन; देहरादून' के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2012—13 में प्रस्तावित योजना 'अल्पसंख्यक कल्याण भवन, देहरादून' के निर्माण से सम्बन्धित आगणंन के परीक्षणोंपरान्त औवित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू० 690.10 लाख {रू० छः करोड नब्बे लाख दस हजार मात्र (68.93 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार एवं सिविल कार्य हेतु रू० 621.17 लाख)} की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2012—13 में प्रश्नगत मद में प्राविधानित धनराशि रू० 100.00 लाख व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। धनराशि के आहरण/व्यय से पूर्व भूमि विभाग के नामे होने अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

कर लिया जायगा।

2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय

तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

5. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006

द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

7. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules,

2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपन्न पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाये। उक्तानुसार निर्धारित समयाविध में कार्य पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा। एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर होने के पश्चात ही आवश्यकतानुसार धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी।

परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की 9. जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सैंटेज चार्ज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन 10. या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा 11. स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। अव्ययित अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति / अनुमोदित दरों को जो दरें 12. शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण

अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में 13. व्यय कदापि न किया जाये।

यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्भवे न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर

शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।

निर्माण कार्य की मानिटरिंग निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा की जायेगी। कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी०पी० डब्लू० फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-(आयोजनागत)-00- 800-अन्य व्यय-09-अल्पसंख्यक कल्याण भवन का निर्माण के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:-228(P) / XVII(3)/2012-13, दिनांक 26 फरवरी, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति तथा अलोटमेंट आई.डी. संख्या- \$1302150406 दिनांक 28.02.2013 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

(सोमपाल) अनु सचिव

पृष्ठांकन संख्या:- 1390/ (1)XVII-3/13-20(बजट)/2012 तद्दिनांकित। प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रषित:-

महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून। 1.

निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड देहरादून। 2.

जिलाधिकारी, हरिद्वार। 3.

वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार, उत्तराखण्ड। 4.

परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लि० हरिद्वार इकाई हरिद्वार।

वरिष्ठ शोध अधिकारी, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय

एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश पंजिका।

अनु सचिव।